

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्रसंख्या :- 83/2021

उनवान

1. सुरजमल उर्फ सुरजा पुत्र देबूराम उम्र वयस्क जाति मीणा, निवासी ग्राम माटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— अप्रार्थी/वादी

बनाम



1. प्रभू पुत्र देबूराम
2. बालूराम पुत्र देबूराम
3. रोशनी देवी पत्नी रिछपाल हाल पत्नी बालूराम
समस्त जाति मीणा, उम्र वयस्कान् निवासी ग्राम मामटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. प्रबन्धक एस.एस.बी.जे. बैंक शाखा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
7. राजस्थान सरकार भू-धारक जरिये तहसीलदार, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— प्रार्थी/प्रतिवादीगण

8. सोनी पुत्री देबूराम पत्नी सुरज्ञानी जाति मीणा, निवासी ग्राम उदावाला तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
9. महेश पुत्र हनुमान
10. कौशल्या पुत्री हनुमान जाति मीणा, निवासी ग्राम उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

— अप्रार्थी/तरतीबी प्रतिवादीगण

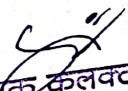
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रामकिशोर यादव, वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :- 14/5/25

प्रार्थना-पत्र संक्षेप में इस प्रकार पेश किया गया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में वादी ने खसरा नंबर 1151/1.94 है0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर पर


सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज0



जाने योग्य नहीं है बल्कि साक्ष्य सबूत पेश करने के बाद साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हो सकता है। प्रथम दृष्टया सुनवाई के अधिकार प्राप्त दावे को खारिज किया जाना कानून सम्मत नहीं है। प्रतिवादीगण ने वेईमानी, बदनीयति से अधूरत्यों के आधार पर गलत मिथ्या कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र गलत रूप से पेश किये जाने पर प्रार्थना-पत्र प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना-पत्र का खण्ड संख्या 3 गलत, मिथ्या तथ्यों पर पेश किया है। वादी अप्रार्थी ने कहीं भी आवंटन को चैलेंज नहीं किया अगर आवंटन को चैलेंज किया जाता तो भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 14(4) के अंतर्गत किया जाता लेकिन अप्रार्थी वादी का दावा जिमन नंबर 1 वाद पत्र में वर्णित भूमि मौका बज से हि0 1/3 का वादी, हि0 1/3 का प्रतिवादी संख्या 1, हि0 1/3 का प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। बराबर बराबर काबिज कर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 अकेले का कोई हक अधिकार कब्जा काश्त नहीं है। वर्णित भूमि का साबिक रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा में 10-10 बीघा भूमि अलाट की गई थी जिसका कि हाल माप प्रणाली से रकबा 5.00 है0 होता है, लेकिन भू-प्रबन्ध के अधिकारियों अधिकारियों ने गलती से गैर कानूनी रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व गलत विधि विपरीत तरीके से गलत मिलान क्षेत्रफल व रकबा कर कर दिया गया बकि भू-प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, जो काबिले रुस्ती है, जिसकी घोषणा किया जाना आवश्यक है। वादी-प्रतिवादीगण हिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है व उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। वादी अपने पूर्वजता के समय से उक्त भूमि में शामिल में रहकर काश्त करता आ रहा है। जिमन नंबर 1 वाद पत्र में अंकित भूमि अलाटमेंट के समय वादी व वादी के दोनों सगे भाई छोटे थे। वादी व पिता व प्रतिवादी संख्या 1 बड़े थे जिन्होंने भूमि खसरा नंबर 1150 की भूमि वादी के पिता अपने नाम तथा खसरा नंबर 1151 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के बड़े भाई के नाम अलॉट करवाई थी। वक्त अलॉटमेंट वादी व अन्य दोनों भाई छोटे थे। प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता का बड़ा लडका था। सम्पूर्ण भूमि पर सभी शामिल में रहकर निवास व कृषि करते थे। उस वक्त आवंटित भूमि उबड़-खाबड़ आखलों की जमीन थी जिसमें मवेशी चराते थे। पानी-पूला व घास-पूस का उपयोग-उपभोग शामिल में करते आये थे। वादी ने भूमि में काफी मेहनत व रूपये खर्च करके समतल करवाया है। मैदानी 8 इंच पाईप की बोरिंग कराई है। पहले छप्परपोश घर बनाकर व अब पुख्ता मकानात बनाकर कृषि सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार निवास करते हैं। उक्त भूमि में वादी द्वारा बोरिंग कराने व छप्परपोश घर बनाकर व पुख्ता मकानात वादी व उसके पुत्र द्वारा बोरिंग कराने व छप्परपोश घर बनाकर व पुख्ता मकानात वादी व उसके पुत्र द्वारा बनाकर निवास करते हुए आ रहे होने का भी कभी विरोध नहीं किया गया है। इसके संबंध में दावा इस्तकरारहक, दुर्रस्ती, नैदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञाका दावा पेश किया है, जिसे राजस्थान



महायुक्त कलक्टर
राज.



काशतकारी अधिनियम की धारा 207 की तृतीय अनुसूचि के अनुसार न्यायालय हाजा को सुनवाई का बखूबी क्षेत्राधिकार प्राप्त है क्योंकि दावा आवंटन निररती के बावत पेश नहीं नहीं किया गया है। साक्ष्य के अभाव में प्रकरण प्रथम दृष्टया साबित नहीं किया जा सकता है, ना ही दावा प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार सुनवाई के आधार पर खारिज किया जा सकता है। प्रार्थना-पत्र य हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी/प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना-पत्र गलत रूप से पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादी का दावा शामलाती 20 बीघा भूमि आवंटन के विबंध में पेश किया है जो विधि प्रक्रियानुसार काशतकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि में वर्णित धारा 207 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा को सुनने व निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। जिमन नंबर 5 प्रार्थना-पत्र जिस तरह जाहिर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वादी प्रार्थी को वाद कारण पैदा होने पर ही वाद पत्र पेश किया गया है। वादी ने अपने वाद पत्र के जिमन नंबर 1 लगायत 14 में वर्णितानुसार तथा वाद पत्र के जिमन नंबर 10 लगायत 14 स्पष्ट रूप अंकित किया है कि आ0 ख0 नं0 1150 व 1151 की भूमि एक जगह मिली हुई जिसमें वादी ने अपने हिस्सा भूमि को अलग होने के बाद काफी रूपये खर्च करके समतल करवायी गयी है तथा उसे काशत योग्य बनाया है तथा उसमें काशत कर सिंचाई कर उपयोग-उपभोग करता आ रहा है तथा प्रतिवादीगण की भूमि ऐसे ही पडी हुई है जो कि वादी के हिस्सा की समतल करवायी व काशत योग्य भूमि को हड़प करने के लिए प्रतिवादीगण जिमन में बेईमानी व बदनीयती पैदा हो गई है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज संगठन बनाकर वादी को उसके हिस्सा कब्जा काशत की भूमि से हैरान व परेशान कर बेदखल करने व कब्जा करने पर आमादा है तथा काशत करने में मजाहमत पैदा करने पर उतारू है। जिमन नंबर 6 प्रार्थना-पत्र जिस तरह से जाहिर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। माननीय राजस्व एण्डल अजमेर व सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की पालना में कानूनन इस्तकाररहक, दुरुस्ती घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मुखालपाना कब्जे के आधार पर हक परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकतानुसार साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित किये जाने के आधार पर खातेदारी घोषणा कानूनन की जा सकती है। प्रार्थी प्रतिवादीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जिमन नंबर 7, 8 प्रार्थना-पत्र जिस तरह से जाहिर किया गया है गलत है, अस्वीकार है। वादी वाद पत्र स्वच्छ हाथों से लेकर आया है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र गलत मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिन सब बातों की जानकारी साक्ष्य आने पर विधि सम्मन न्याय निर्णय से हो सकेगी। इसलिए प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी प्रतिवादी बार-बार एक ही शब्द लेकर आ रहा है कि आवंटन भूमि के क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी का दावा आवंटन

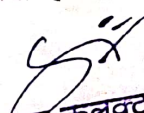


को चैलेन्ज नहीं किया गया है बल्कि साबित खसरा नंबर 534 में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के ससुर तथा तरतीबी प्रतिवादी के पिता व पिता व प्रतिवादी संख्या 1 को 10-10 बीघा शामलाती रूप में अलाट की गई थी जिस पर वादी व प्रतिवादीगण शामलाती रूप में अपने पिता व भाई प्रतिवादी संख्या 1 के साथ काविज गश्त करते आ रहे थे तथा पिता की मृत्यु के बाद अलग होकर बराबर हिस्सा पर काविज हकर काश्त आ रहे हैं। इसी आधार पर दावा पेश किया है, जिसे न्यायालय हाजा का नवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने यह दावा सन् 2021 में न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है जिसमें जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है जो साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय किया जाना कानून सम्मत है इसलिए यह प्रार्थना-पत्र बिना किसी कारण पैदा हुए अन्दर मियाद नाना कहकर पेश किया है, जो न्यायालय हाजा का बेशकीमती समय जाया करने के लिए प्रार्थी प्रतिवादी ने बिना अधिकार प्रार्थना-पत्र पेश किया है अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण का सभी पहलुओं पर साक्ष्य आने पर न्याय निर्णय साक्ष्य नवाई के बाद किया जाना न्याय होने के लिए अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। श्रील प्रार्थी प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 1150, 1151 व साबिक खसरा नंबर 534 से बनाया गया है। यह दावा दिनांक 12.08.2021 को वादी द्वारा पेश किया गया है। भूमि का आवंटन सन् 1968 में किया गया है, जिसके अनुसार हाल खसरा नंबर 1150/1.94 है 0 देवू के नाम तथा खसरा नंबर 1151/1.94 है 0 प्रभु के नाम भू-प्रबन्ध कार्यावाही के दौरान दर्ज किया गया है। आराजी खसरा नंबर 1150/1.94 है 0 भूमि वादी प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है जबकि खसरा नंबर 1151/1.94 है 0 भूमि अकेले प्रार्थी प्रतिवादी प्रभु पुत्र देवू के नाम आवंटित भूमि है। अलाटमेन्ट कहीं विवादित नहीं है। प्रार्थी प्रतिवादी प्रभु की पर्सनल खातेदारी भूमि है, जिसमें किसी परिवार के सदस्य की कोई खातेदारी नहीं है। वादी अप्रार्थी 45 साल बाद प्रार्थी प्रतिवादी के नाम आवंटित भूमि पर पेशान के आधार पर हिस्सा मांग रहे हैं। भूमि आवंटन की प्रक्रिया एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। बन्दोबस्त से संबंधित नहीं है। वादी अप्रार्थी ने आवंटन के खिलाफ कोई अपील नहीं की। आवंटित भूमि का सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाने के बाद दावा लेकर आये है। घोषणा खातेदारी के लिए कब्जा होना आवश्यक है। इसके लिए कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता



अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी प्रतिवादी प्रभु अकेले के नाम आवंटित भूमि में वादी का हित प्रकट नहीं होता है जो विधि द्वारा


सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वर्जित है। प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कथन किया गया है, इस बाबत वादी अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रस्तुत वाद में न्यायालय हाजा को सुनवाई का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भूमि आवंटन शामिल रूप से होने संबंधी कोई दरतावेज प्रार्थी प्रतिवादी ने पेश नहीं किये हैं। अप्रार्थी वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर शामिल रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी प्रतिवादी ने अलाटमेन्ट गलत करवाया है। सेटलमेन्ट ने भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान आवंटित रकबे के विपरित रकबा क्रम दर्ज किया है। शामिल भूमि 4 है० से ज्यादा अलाटमेन्ट नहीं हो सकती है। भूमि अलाटमेन्ट के समय वादी व वादी के दोनो भाई छोटे थे तथा वादी का पिता व प्रतिवादी संख्या 1 बड़े थे जिन्होंने खसरा नंबर 1150 की भूमि वादी के पिता ने अपने नाम तथा खसरा नंबर 1151 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के बड़े भाई के नाम से अलाटमेन्ट करवाई थी। अलाटमेन्ट वादी व अन्य दोनो भाई छोटे थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ही वादी के पिता का बड़ा लडका था। सम्पूर्ण भूमि पर सभी शामिल में रहकर काश्त एवं निवास करते थे। खसरा नंबर 1151 में मकान बने हुए हैं जो सभी बिन्दु साक्ष्य में तय होंगे। अलाटमेन्ट संयुक्त पृथक-पृथक हुआ यह साक्ष्य में तय होगा। अवयस्क होने से वादी व वादी के दोनो भाईयों के नाम आवंटन नहीं हो सका, जबकि सभी की शामिल कब्जे काश्त की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थी प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाबी बहस में कथन किया कि आवंटन एक व्यक्ति को ही किया जाने से उसके परिवार के किसी सदस्य का कोई हिस्सा नहीं माना जा सकता है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में संवहन से खसरा नंबर 1151/1.94 है० वाकै ग्राम मामटोरी कलां के स्थान पर ग्राम मनोहरपुर दर्ज हो गया है जिसे संशोधन फरमाया जावे। अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादी खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहाँ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में सामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:-


(क). जहाँ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहाँ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहाँ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहाँ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया

(च). जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधों की अनुपालना करने में असफल रहता है।




सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

आदेश



हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित तथ्यों का हनता से मनन किया। प्रार्थी प्रतिवादी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी मार्च 005 पेज 146, आरआरडी 14 अगस्त 2020 पेज 280, पेश की है, जिनका अवलोकन व मनन किया गया। न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। समस्त तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त रिवार के व्यक्ति हैं, जो मृतक देबूराम के वारिसान हैं। देबूराम के नाम तथा प्रतिवादी संख्या प्रभू के नाम एक ही खसरे की भूमि में से पृथक-पृथक भूमि का आवंटन किया गया है, जो हाल भू-प्रबन्ध की कार्यवाही से पूर्व किया हुआ है। प्रतिवादी प्रार्थी प्रभू के नाम आवंटित भूमि खसरा नंबर 1151/1.94 है 0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। आवंटन के पश्चात् खातेदारी प्रतिवादी प्रभू के नाम दर्ज चली आ रही है, जेससे वादी व अन्य किसी किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। वादी अप्रार्थी ने माराजी मुतनाजा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन होना वाद पत्र में स्वीकार किया है। वादी अप्रार्थी का यदि विवादित भूमि पर कब्जा काशत रहा है तो उसे आवंटन के खिलाफ न्यायिक अधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए थी। अप्रार्थी वादी मात्र खसरा नंबर 1150 में बंटवारा कराने मात्र के अधिकारी है। खसरा नंबर 1151/1.94 है 0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित भूमि है, जिसका एक मात्र मालिक व स्वामी प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ही है, जिसके नाम आवंटित भूमि में से खातेदारी घोषणा का दावा लाने का वादी अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी केवल मात्र सहखातेदारी भूमि का बंटवारा कराने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आवंटित भूमि खसरा नंबर 1151/1.94 है 0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां के संबंध में हक घोषणा खातेदारी का जो यह दावा पेश किया है इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया एक निर्णय की श्रेणी में आता है तथा निर्णय के खिलाफ अपील के प्रावधान बने हुए हैं। हाल भू-प्रबन्ध की कार्यवाही से पहले यह आवंटन की प्रक्रिया की गई थी जिसके विरुद्ध वादी अप्रार्थी ने न्यायिक न्यायालय में किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की है। ऐसी स्थिति में भी दावा वादी लाने योग्य नहीं है। वादी अप्रार्थी को आवंटन आदेश के विरुद्ध नियत समयावधि में 14(4) के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वाद भूमि खसरा नंबर 1151/1.94 है 0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां के संबंध में वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। खसरा नंबर 1150, 1151 की भूमि एक जगह मिली हुई है तो इस संबंध में दोनों पक्ष नियमानुसार सीमाज्ञान कराने के अधिकारी हैं। साथ ही वादी अप्रार्थी यदि अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवारा कराना चाहते हैं तो पृथक से नया वाद दायर कर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.



नुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रस्तुत दावा प्रतिवादी प्रार्थी प्रभु के नाम आवंटित खातेदारी भूमि में से हक खातेदारी घोषणा एवं बंटवारा हेतु पेश किया गया है जो चलने योग्य ही है। वादी अप्रार्थी को आवंटन प्रक्रिया के बाद आवंटन निरस्त किये जाने बाबत निश्चित मयावधि में सक्षम न्यायालय में अपील की कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो उसके द्वारा नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आवंटि के नाम आवंटित भूमि में खातेदारी घोषणा लाने का उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतएव दावा वादी (Maintainable) पोषणीय नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाता है तथा वादी अप्रार्थी आवंटित भूमि में प्रतिवादी संख्या की अकेले की खातेदारी भूमि में हक घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादा लाने का अधिकारी नहीं है। वादी सूरजमल चाहे तो अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1150 वाकै ग्राम मामटोरी कलां तहसील शाहपुरा के संबंध में बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पृथक से नया वाद दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। आवंटित भूमि के संबंध में वाद पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपितु दावा अधि द्वारा वर्जित होने से दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार पना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.5.2025 को सरे इजलास नाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(संजीव कुमार खेदर)
सहायक न्यायाधीश (ट्रेक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्रसंख्या :- 83/2021

उनवान

1. सुरजमल उर्फ सुरजा पुत्र देबूराम उम्र वयस्क जाति मीणा, निवासी ग्राम माटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

- अप्रार्थी/वादी

बनाम



1. प्रभू पुत्र देबूराम
2. बालूराम पुत्र देबूराम
3. रोशनी देवी पत्नी रिछपाल हाल पत्नी बालूराम
समस्त जाति मीणा, उम्र वयस्कान् निवासी ग्राम माटोरी कलां, तहसील शाहपुरा,
जिला जयपुर, राज0।
4. प्रबन्धक एस.एस.बी.जे. बैंक शाखा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
7. राजस्थान सरकार भू-धारक जरिये तहसीलदार, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

- प्रार्थी/प्रतिवादीगण


8. सोनी पुत्री देबूराम पत्नी सुरज्ञानी जाति मीणा, निवासी ग्राम उदावाला तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
9. महेश पुत्र हनुमान
10. कौशल्या पुत्री हनुमान जाति मीणा, निवासी ग्राम उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

- अप्रार्थी/तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गतआदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रामकिशोर यादव, वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से


सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

आदेश दिनांक :- 14.5.2025

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तैवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाता है तथा वादी अप्रार्थी आवंटित भूमि में प्रतिवादी संख्या की अकेले की खातेदारी भूमि में हक घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वा लाने का अधिकारी नहीं है। वादी सूरजमल चाहे तो अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा 1150 वाकै ग्राम मामटोरी कलां तहसील शाहपुरा के संबंध में बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा पृथक से नया वाद दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। आवंटित भूमि के संबंध में वाद पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपितु दावा धि द्वारा वर्जित होने से दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार मना अपना वहन करें। उक्त डिक्री आज तारीख14.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।



(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रेक)
शाहपुरा जिला न्यायालय
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.